प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 44 अंक-42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 21-28 अक्तूबर 2019 मूल्य पांच रूपए

चुनाव परिणामों ने संगठन और सरकार के लिये खड़े किये कई सवाल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश के दोनों उपचुनाव जीत गयी है लेकिन

इस जीत के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इन चुनाव परिणामों पर जयराम सरकार को सही में खुश होना चीहिये या उसे आत्ममंथन करना चाहिये। क्योंकि इसी सरकार ने पांच माह पहले हुये लोकसभा चुनावो में प्रदेश की चारों सीटों पर रिकार्ड तोड जीत दर्ज की थी। इसी जीत के दम पर यह उप चुनाव बीस-बीस हजार से अधिक की बढ़त के साथ जीतने का दावा किया था। बल्कि गुप्तचर ऐजैन्सीयों ने भी शायद इसी तरह का आकलन सरकार को परोसा था। इसी तर्ज पर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा ने हमीरपुर में पार्टी की एक बैठक में यह फैसला सुनाया था कि संगठन ने पचास से कम आयु के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पवन राणा के इसी ऐलान के परिणाम स्वरूप दोनों जगह युवाओं को तहरीज दी गयी। अब जो परिणाम आये हैं वह इन सब दावों की हवा निकालने वालें हैं बल्कि चर्चाएं तो यहां तक हैं कि यदि कांग्रेस में आपसी फूट नही होती और वह गंभीरता से इस उपचुनाव को लेती तो शायद परिणाम कुछ और ही होते।

इस परिदृश्य में यदि प्रदेश के राजनितिक परिदृश्य में उपचुनाव का आकलन किया जाये तो यह स्पष्ट है कि 2022 में भाजपा और जय राम के लिये राहें आसान नही होंगी। क्योंकि पिछले दिनों कांगड़ा की भाजपा राजनीति के अन्दर संगठन मंत्री पवन राणा और ज्वालामुखी के विधायक रमेश ध्वाला को लेकर जो अलग-अलग ध्रुव खडे हुये थे उनका राजनितिक प्रतिफल उपचुनाव के परिणामों के बाद अपना रंग दिखाने की तैयारी में है। भाजपा के भीतरी सुत्रों की माने तो धर्मशाला में जो समर्थन पार्टी के बागी राकेश चौधरी को मिला है उसके लिये कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के तीन चौधरी नेताओं रमेश धवाला, सरवीण चौधरी और संजय चौधरी की जबाव तल्वी की जा रही है। इसी तरह का खेल पच्छाद में भी खेलने की तैयारी की जा रही है। इस खेल के परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह तय है कि जहां संगठन ने युवा नेतृत्व का आगे उभारने का फैसला लिया है वहीं पर उसे इस चुनाव में लोकसभा के अनुपात में बहुत कम अन्तर से जीत की समीक्षा करके इसकी जिम्मेदारी केन्द्र या राज्य सरकार किसी एक पर तो डालनी ही होगी। क्योंकि केन्द्र के कारण ही प्रदेश में सरकार बन पायी थी। फिर लोस चुनाव से पहले घटे पुलवामा और बालाकोट के कारण प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें भाजपा को इतने बड़े अन्तराल से मिल पायी हैं। लेकिन अब इन उपचुनावों में तो राज्य सरकार के कामकाज का आकलन जनता के लिये एक आधार बनता ही है और इस पैमाने पर राज्य सरकार अपनी सफलता का कोई दावा नही कर सकती है। बल्कि आने वाले दिनों में यदि पार्टी के भीतर यह सवाल भी खड़ा हो जाये कि क्या वर्तमान नेतृत्व के साये में 2022 पार्टी के लिये सुरक्षित हो सकता है या नही तो कोई आश्चर्य नही होना चाहिये।

अभी सरकार के दो मंत्री पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिये परफारमैन्स के पैमाने की बातें अब फिर उठनी शुरू हो गई हैं। इस परफारमैन्स के आईने में यह स्पष्ट है कि यदि पच्छाद में उपचुनाव की कमान आई.पी.एच. मंत्री ठाकुर महेन्द्र सिंह न संभालते तो यहां पर जीत संभव नही हो पाती। यह महेन्द्र सिंह ही थे जिन्होने हर रोज आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें सहते हुये

भी अपनी कार्यप्रणाली नही बदली। ऐसे में सिरमौर से मंत्री पद का दावा उनकी संस्तुति के बिना आगे नही बढ़ पायेगा यह तह है। इसी तरह धर्मशाला में उपचुनाव की कमान स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के पास थी। वहां पर परमार के साथ राकेश पठानिया ने भी सक्रिय भूमिका निभायी है। लेकिन इस सब के बाद भी धर्मशाला में जीत का अन्तर वह नही रह पाया जिसका दावा किया जा रहा था। अब यदि धर्मशाला के लिये चौधरी नेताओं की संभावित

शेष पृष्ठ 8 पर..............

क्या राठौर हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा कर पायेंगे

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने यह उपचुनाव हारने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में यह कहा था कि संगठन

हार के कारणों का पता लगायेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करेगा। राठौर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी धर्मशाला में हार के कारणों की जांच किये जाने और दोषियों को सजा देने की बात की है। राठौर की प्रतिक्रिया के बाद धर्मशाला ब्लाक कांग्रेस को भंग भी कर दिया गया और युवा कांग्रेस ईकाई पर भी इसकी गाज गिरी है। लेकिन धर्मशाला ईकाई पर हुई कारवाई के बाद भंग ईकाई के नेताओं ने भी इस पर पल्टवार किया है। इस पल्टवार से एक नया अध्याय शुरू हो गया है और इसमें अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस द्वन्द में किस किस पर क्या-क्या आरोप प्रत्यारोप आते हैं। लेकिन यह सब पुरे परिदृश्य का एक पक्ष है जो शायद अपने में बहुत बड़ा नही है।

राठौर ने इसी वर्ष के शुरू में संगठन की बागडोर संभाली थी । यह परिवर्तन तत्कालीन अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खु और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच चले द्वन्द का परिणाम रहा है। इस परिवर्तन के लिये वीरभद्र सिंह, आन्नद शर्मा, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी सबने लिखित में सहमति जताई थी।। इसलिये राठौर को स्थापित करने में इन सबकी भूमिका भी समीक्षा का विषय बन जाती है। राठौर ने जिम्मेदारी संभालने के बाद पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने के स्थान पर उसी में नये लोग और जोड़ दिये । राठौर के इस विस्तार की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में आयी और उसमें असफलता मिली। लेकिन लोकसभा चुनावों में किस बड़े नेता की भूमिका कितनी नकारात्मक और सकारात्मक रही है इस पर मीडिया में टिप्पणीयां उठती रही लेकिन संगठन के स्तर पर आज तक किसी के खिलाफ कोई कारवाई नही हो सकी।

स्मरणीय है कि 2014 में भाजपा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर्याय प्रचारित करके सता पर कब्जा किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुये भाजपा के निशाने पर वीरभद्र आये और सीबीआई तथा ईडी ने इसमें मुख्य भूमिकायें अदा की। ईडी और सीबीआई के मामले आज तक चल रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक था कि भाजपा को भी सता में आने पर उसी के हथियार से घेरा जाता लेकिन राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस आज तक ऐसा कोइ मुद्दा नही उठा पायी जबकि ऐसे मुद्दों की कोई कमी नही है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का डर दिखावकर ही विधानसभा और फिर लोकसभा में कांग्रेस को मात दी। आज विधान सभा के उप चुनाव में भी वही खेल दोहराया गया। कांग्रेस

शेष पृष्ठ 8 पर..............

सफलता के लिए अनुशासन एवं समर्पण आवश्यक:राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे अनुशासन एवं समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें ताकि वे भविष्य में देश एवं प्रदेश के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकें। राज्यपाल सोलन जिला के कंडाघाट में राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान में छात्राओं, अध्यापकों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अनुशासन एवं समर्पण के साथ ही शिखर तक पहुंचा जा सकता है। युवाओं के लिए सफलता प्राप्त करने का यही मूलमंत्र है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे नियमित रूप से महापुरूषों का जीवन चरित्र पढ़ें और इससे प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को सत्त रूप से अपने चरित्र का विकास करना होगा। इस दिशा में नैतिक मूल्यों और संस्कारों की जानकारी के साथ-साथ महापुरूषों का जीवन चरित्र सहायक बनेगा।

राज्यपाल ने कहा कि युवा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लें। उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारें ताकि वे देश के उत्तरदायी नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि छात्रों को नियमित रूप से पुस्तकालय में समय बिताना चाहिए।

बंडारू दत्तात्रेय ने सभी का आह्वान किया कि स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को देश, प्रदेश एवं अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा।

राज्यपाल ने इस अवसर पर राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान के पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का अवलोकन भी किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर संस्थान की छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस अवसर पर राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान कंडाघाट की प्रधानाचार्य विनीता आर्या ने संस्थान की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

जनता ने भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों पर जताया विश्वास:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पच्छाद और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उप-चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को चुनने के लिए जनता का धन्यवाद किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास जताया है जो प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उप-चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के लगभग दो साल के कार्यकाल में जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न विकासात्मक और रोजगार सृजित योजनाएं आरम्भ की हैं जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश की जनता के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों कार्य किए हैं।

उद्योगों की मांग पर पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायें:राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं संबंधित विभागों की राजभवन में बैठक का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बैठक की अध्यक्षता की।

राज्यपाल ने प्रदेश में कौशल विकास में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता में किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिये वह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में रिपोर्ट दें और यदि जरूरी है तो वह केंद्र सरकार से हिमाचल का पक्ष रखेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग विशेष कर युवा वर्ग लाभान्वित हो सके।

उन्होंने कम्प्यूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर प्रभावी बनाने और नए व्यवसायिक प्रशिक्षण आरंभ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों की मांग पर पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिए और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया और निगम की गतिविधियों की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि निगम 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्य कौशल मिशन के रूप में स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य तकनीकी व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण (टीवीईटी) कार्यक्रमों को समेकित करना और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ सभी टीवीईटी कार्यक्रमों को श्रेणीबद्ध करना है। यह राज्य में टीवीईटी के डिजाइन और वितरण और कौशल के बुनियादी ढाचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा भी प्रदान करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कौशल विकास के तहत मोबिलाइजेशन, ट्रेनर्स, इंफास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री कनेक्ट में चुनौतियों पर काबू पाने के लिए नई पहल की जानकारी भी दी। उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की प्रगति से भी अवगत करवाया।

तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक शुभकरण सिंह ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 356 तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान के कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 158 संस्थान सरकारी क्षेत्र में हैं, जबकि 198 संस्थान निजी क्षेत्र में प्रति वर्ष 57488 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में सात केंद्र वित्त पोषित संस्थान भी विभाग के सहयोग से चल रहे थे। उन्होंने डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों, फार्मेसी कॉलेजों, डिप्लोमा स्तर के संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना, एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कौशल विकास परियोजना, पॉलिटेक्निक (सीडीटीपी) के माध्यम से सामुदायिक विकास के बारे में भी जानकारी दी।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन और उद्योग विभाग के उप निदेशक संजय शर्मा ने व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर अपनी प्रस्तुति दी।

मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का खर्चा वहन करेगी केन्द्र सरकार

शिमला/शैल। नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से जिला मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने शिमला, कांगड़ा और कुल्लू हवाई अड्डों के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय भारत सरकार के नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि शिमला और कांगड़ा के हवाई अड्डों के विस्तार की लागत को केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय वहन करेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक दल शीघ्र ही कुल्लू तथा मनाली हवाई अड्डों के विस्तार के सर्वेक्षण के लिए दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि उड़ान-2 के तहत नागर विमानन मंत्रालय प्रदेश में छः प्रस्तावित हेलीपोर्ट के निर्माण तथा परिचालन की लागत के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने इसके अतिरिक्त उड़ान-1 के अंतर्गत वर्तमान सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। सचिव, संयुक्त सचिव और महानिदेशक नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन हिमाचल प्रदेश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन 17 नवंबर को

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन के कार्यक्रम के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन 17 नवंबर, 2019 को होगा।

अधिसूचना के अनुसार रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार 1, 2 और 4 नवंबर, 2019 को संबंधित निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन कर सकेंगे। नामांकन प्रातः 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे के मध्य किया जा सकेगा। प्रस्तुत नामांकनों की संवीक्षा 5 नवंबर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे से की जाएगी। उम्मीदवार 7 नवंबर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक नामांकन वापिस ले सकते हैं। निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह 7 नवंबर, 2019 को नाम वापिस लेने के तुरंत बाद आबंटित किए जाएंगे।

अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए मतगणना 17 नवंबर, 2019 को मतदान के तुरंत बाद आरंभ होगी। मतगणना ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगी। परिणाम की घोषणा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए मतगणना 18 नवंबर, 2019 को निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी अर्की द्वारा पंचायत समिति हॉल कुनिहार में प्रातः 9.00 बजे से आरंभ की जाएगी। जिला परिषद सदस्य पद के लिए परिणाम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन द्वारा घोषित किया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार जिला सोलन की पंचायत राज संस्थाओं में 19 पद रिक्त हैं। इनमें से एक पद जिला परिषद सोलन के वार्ड संख्या-4 कुनिहार, दो पद उपप्रधान ग्राम पंचायत बसंतपुर, विकास खंड कुनिहार तथा उपप्रधान ग्राम पंचायत खिलियां विकास खंड नालागढ़ का है। 16 पद सदस्यों के रिक्त हैं। 16 पदों में विकास खंड कुनिहार की ग्राम पंचायत कुनिहार के वार्ड संख्या-2, ग्राम पंचायत बसंतपुर के वार्ड संख्या-2 तथा वार्ड संख्या-3, ग्राम पंचायत डुमेहर के वार्ड संख्या-4, विकास खंड सोलन की ग्राम पंचायत कोरो के वार्ड संख्या-2, ग्राम पंचायत शामती के वार्ड संख्या-3, ग्राम पंचायत धरोट के वार्ड संख्या-3, ग्राम पंचायत सपरून के वार्ड संख्या-5, विकास खंड धर्मपुर की ग्राम पंचायत दाड़वां के वार्ड संख्या-1, विकास खंड नालागढ़ की ग्राम पंचायत नंड के वार्ड संख्या-6, ग्राम पंचायत लूनस के वार्ड संख्या-5, ग्राम पंचायत के कसौली के वार्ड संख्या-3, ग्राम पंचायत रामशहर के वार्ड संख्या-2 व वार्ड संख्या-7, ग्राम पंचायत भटोलीकलां के वार्ड संख्या-1 तथा कंडाघाट विकास खंड की ग्राम पंचायत छावशा के वार्ड संख्या-7 के लिए निर्वाचन होना है।

अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन के दृष्टिगत सोलन जिला में जिला परिषद वार्ड के निर्वाचन के कारण पूरे जिला में नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

पर्यावरण संरक्षण सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व:केसी चमन

शिमला/शैल।उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण रूप से उपयोग न कर रही हम प्लास्टिक मुक्त हिमाचल एवं प्लास्टिक मुक्त सोलन की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। केसी चमन नगर परिषद सोलन में पॉलीथीन संग्रह केंद्र का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

केसी चमन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारण बनकर उभरा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को न कहकर हम इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के कारण न केवल पशुओं को नुकसान हो रहा है अपितु इससे धरती बंजर भी बन रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े अथवा जूट से बने थैलों का प्रयोग आरंभ करना होगा।

उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने के लिए पहल आरंभ की है। इस पहल के तहत सभी जिलों सहित सोलन जिला में भी पॉलीथीन संग्रह केंद्र आरंभ किए गए हैं। इन केंद्रों पर प्रदेश सरकार की योजना के तहत 75 रुपये प्रति किलो की दर से प्लास्टिक एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अपने आसपास प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए प्लास्टिक को एकत्र कर नगर परिषद सोलन के इस पॉलीथीन संग्रह केंद्र में जमा करवाएं।

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत यह आवश्यक है कि लोग स्वेच्छा से प्लास्टिक का प्रयोग करना छोड़ें। अगर कहीं आसपास पॉलीथीन दिखाई दें तो उसे एकत्र कर सफाई कर्मचारियों को दें ताकि इस प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सके। उन्होंने लोगों से भी इस अभियान में सहयोग देने की अपील की। केसी चमन ने पॉलीथीन संग्रह केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए।

इस अवसर पर वार्ड नंबर 7 के निवासी नरेश कुमार ने 31 किलोग्राम प्लास्टिक, राजबीर ने 11 किलोग्राम तथा धर्मपाल ने 6 किलोग्राम प्लास्टिक पॉलीथीन संग्रह केंद्र में जमा करवाया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट सफल बनाने में सहयोग दे उद्यमी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य के उद्यमी प्रदेश के 'ब्राण्ड एम्बेस्डर' हैं और प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने में अहम् भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने उद्यमियों से 7 व 8 नवम्बर को धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने में अपना सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला सोलन के बद्दी में बद्दी-बरोटीवाला- नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की प्रगति और विकास में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उद्योग प्रदेश में न केवल लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि करोड़ों रुपये के करों के माध्यम से प्रदेश के खजाने में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को उत्तम वातावरण उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अब 'ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्मस' में 'फास्ट मूवर्स' की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है और सिंगल विंडो के माध्यम से निवेशकों को सेवाएं उपलब्ध करवाने में दक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बीबीएनआईए प्रदेश में तेजी से औद्योगिकीरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क में फोर-लेनिंग का कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता सम्भालते ही, सरकार ने जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रगतिशील कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन एक महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उद्यमियों को प्रदूषण रहित पर्यावरण, निवेश-मित्र नीतियां, जिम्मेदार और जवाबदेह प्रशासन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। यह सभी विशेषताएं हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब तक 79,000 करोड़ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत और कुशल नेतृत्व से देश प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले उद्यमी स्थानीय उद्यमियों के सक्रिय सहयोग के बिना प्रदेश में निवेश नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्हें उद्योग स्थापित करने में स्थानीय उद्यमियों के सहयोग की सदैव आवश्यकता रहती है।

उन्होंने क्षेत्र के उद्यमियों को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में सक्रिय रूप से भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया तथा उन्हें प्रदेश के विकास में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी उपस्थित से इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की शोभा बढ़ाएंगे।

इस अवसर पर बीबीएनआईए ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपये का अंशदान भी किया। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि अब निवेशकों की सुविधा के लिए 118 के तहत समयबद्ध अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मंजूरी की व्यवस्था बनाई गई है।

बीबीएनआईए के अध्यक्ष संजय खुराना ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का स्वागत करते हुए उद्यमियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का बद्दी-बरोटीवाला -नालागढ़ क्षेत्र बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने बीबीएनआईए की अभी तक की यात्रा पर प्रकाश डाला और संघ की मांगों का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डवेल्पमेंट अथॉरिटी को सुदृढ़ करने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र को बेहतर बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीबीएनआईए बद्दी-बरोटीवाला -नालागढ़ क्षेत्रों में रेन हार्वेस्टिंग प्रोजैक्ट के लिए एक-एक स्कूल को गोद लेगी।

प्रभावी जन सम्पर्क के लिए मीडिया से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें:बी.डी.शर्मा

शिमला/शैल। जन सम्पर्क अधिकारियों को जनता में विश्वास स्थापित करने के लिए मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण तथा स्थायी सम्बन्ध बनाने चाहिए। इन सम्बन्धों से जन सम्पर्क अधिकारियों को सरकार की विकासात्मक योजनाओं से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

यह बात पूर्व निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क बी.डी. शर्मा ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारियों तथा उप-सम्पादकों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन्स में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे व अंतिम दिन के अवसर पर कही।

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों व उपलब्धियों, प्रचार के साधनों, होर्डिंग, प्रदर्शनी, डिसप्ले बोर्ड, वीडियो डिसप्ले तथा विज्ञापन में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की भूमिका पर बातचीत करते हुए बी.डी. शर्मा ने कहा कि जन सम्पर्क क्षेत्र चुनौतियों से भरा है लेकिन जन सम्पर्क अधिकारी अतिरिक्त प्रयासों द्वारा इन्हें जनता की सेवा के अवसरों में परिवर्तित कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तंत्र में सरकार लोगों के प्रति जबावदेह है तथा जन सम्पर्क सुशासन के प्रभाव के प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन सम्पर्क अधिकारियों को सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। उन्हें सरकारी विभाग, मीडिया, निजी कम्पनियों, स्वयं सेवी संस्थाएं इत्यादि से सम्पर्क रखना पड़ता है ताकि लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा सके। जन सम्पर्क क्षेत्र में जन सम्पर्क अधिकारी को अपने संचार कौशल को समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। संचार के क्षेत्र में निष्ठा व कठिन परिश्रम से ही सफलता की जा सकती है।

उन्होंने प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर, सफलता की कहानी तथा लेखों पर बातचीत करते हुए बेहतर संचार के लिए लेखन कौशल में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जन सम्पर्क के आदर्शो में संक्षिप्तता भी शामिल है। प्रेस विज्ञप्तियां सदैव संक्षिप्त तथा प्रभावी होनी चाहिए ताकि वास्तविक संदेश जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रेस विज्ञप्तियों में संदेश तथा तथ्य शामिल होने चाहिएं तथा अतिरिक्त जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के लिए अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए फीचर, सफलता की कहानियों तथा लेखों का उपयुक्त उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके उपरांत, वरिष्ठ पत्रकार रविन्द्र मखैक ने 'एन ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया' पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि हूटसूट नामक सोशल मीडिया प्रबंधन प्लेटफार्म द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार विश्व की आबादी 7.68 बिलियन है, जिसमें से 5.1 बिलियन (67 प्रतिशत) मोबाइल उपयोगकर्ता, 3.48 बिलियन (45 प्रतिशत) सोशल मीडिया उपयोगकर्ता जबकि भारत की आबादी 1.36 बिलियन है जिसमें 310 मिलियन (23 प्रतिशत) सोशल मीडिया उपयोगकर्ता, 560 मिलियन (41 प्रतिशत), इंटरनेट उपयोगकर्ता तथा 1.2 बिलियन (87 प्रतिशत) मोबाइल उपयोगकर्ता शामिल है। ग्लोबल सोशल मीडिया अकांउटस में फेसबुक के 65.23 प्रतिशत, यूट्यूब के 54.60 प्रतिशत, इंस्टाग्राम के 28.73 प्रतिशत, टीकटॉक के 14.36 प्रतिशत, ट्विटर के 9.36 प्रतिशत तथा लिंकडीन के 8.7 प्रतिशत अकांडटस है जबकि भारत में यूट्यूब के 93 प्रतिशत, फेसबुक के 89 प्रतिशत, इंस्टाग्राम के 69 प्रतिशत, ट्विटर के 57 प्रतिशत और लिंकडीन के 48 प्रतिशत अकांडटस है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया शिक्षित तथा अशिक्षित उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है। आजकल मोबाइल फोन पर ज्यादा बल दिया जा रहा है तथा एक क्लिक पर जानकारी प्रदान करने के लिए और ज्यादा मोबाइल आधारित एप बनाए जा रहे है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए संदेश तैयार करने में कई भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया लोकमत बनाता है तथा भविष्य में हमारे देश में सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि होगी। सोशल मीडिया से जहां पारदर्शिता आई है वहीं भ्रांति भी सृजित हो रही है। जन सम्पर्क अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करना तथा इसमें भाग लेना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जा सके। सोशल मीडिया को समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है लेकिन जन सम्पर्क अधिकारियों को इस उपयोगी मीडिया का उपयोग करने के लिए इसकी खामियों से निपटने की रणनीति पर कार्य करना चाहिए। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने इस अवसर पर सरकार के कार्यक्रमों तथा नीतियों के उपयुक्त तथा सामयिक प्रचार पर बल दिया ताकि आमजन सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने सरकार के कार्यक्रमों तथा नीतियों के बेहतर प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा अन्य ऐप्लीकेशनों के उपयोग पर भी बल दिया।

888.24 करोड़ के निवेश वाले 29 नए व विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति

शिमला/शैल। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेश में नए औद्योगिक उपक्रमों और वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों पर लगभग 888.24 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 3420 लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्राधिकरण ने जिन नए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की इनमें ऊना जिला की हरोली तहसील के श्यामपुरा गांव में आईस क्रीम उत्पादन के लिए मैसर्ज पारस स्पाईसिज, सोलन जिला के नालागढ़ में बीड़ प्लासी गांव में टीशू और राईटिंग पेपर्स के लिए मैसर्ज डी. के. टीशू एण्ड पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड, हेंडगन रिवालवर और पिस्टल निर्माण के लिए कांगड़ा जिला के औद्योगिक क्षेत्र कदरौड़ी में मैसर्ज मुकेश भार्गव इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, फ्रूट जैम जेली, मुरब्बा, टोमेटो कैचअप आदि के निर्माण के लिए ऊना जिला के क्रेमिका फूड पार्क हरोली में मैसर्ज ऊना मिरिक्ल फूड्स, पाऊडर के रूप में सिट्रिक ऐसिड जूस उत्पादन के लिए हरोली तहसील के पंडोगा में मैसर्ज हिन्दुस्तान फार्म डारेक्ट इंग्रेडियंट्स प्राईवेट लिमिटेड, दवा उत्पादन के लिए सोलन जिला के बद्दी में मैसर्ज दलास ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ताम्बे की तार और केबल निर्माण के लिए सोलन जिला के गांव कथा-बद्दी में मैसर्ज अमित इंडस्ट्रीज, चीनी व वाईन उत्पादन के लिए ऊना जिला में अम्ब के अंतर्गत हपला गांव में मैसर्ज ग्रेट थापला शुगर मिल प्राईवेट लिमिटेड, दही, खोआ व पनीर उत्पादन के लिए बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी में मैसर्ज चन्द्र मिल्क प्रोडक्ट और सी. ए. कोल्ड स्टोर निर्माण के लिए शिमला जिला के कुमारसेन में मैसर्ज शिवा एग्रीफेश के प्रस्ताव शामिल हैं।

विस्तार प्रस्तावों में क्राफ्ट पेपर निर्माण के लिए सिरमौर जिला के नाहन के अंतर्गत गांव जटांवाला व जोहड़ों में मैसर्ज रूचिरा पेपर लिमिटेड, शराब उत्पादन के लिए कांगड़ा जिला की जसवां कोटला तहसील के अंतर्गत संसारपुर टैरेस में मैसर्ज प्रीमियर एल्कोबेव प्राईवेट लिमिटेड, दवा निर्माण के लिए सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के अंतर्गत गंगुवाला में मैसर्ज सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रासायन उत्पादन के लिए सिरमौर जिला की नाहन तहसील के अंतर्गत मौजा ओगली में मैसर्ज हिमाचल पोलियोलेफिन्स लिमिटेड, लैड इनगट उत्पादन के लिए ऊना जिला के गगरेट में मैसर्ज पी.एम. डब्ल्यू. मेटल एण्ड एलोएज प्राईवेट लिमिटेड, शैम्पू व डिटरजेंट पाउडर उत्पादन के लिए सोलन जिला के काथा में मैसर्ज प्रोक्टर एण्ड गेम्बल प्राईवेट लिमिटेड, क्राफ्ट पेपर बोर्ड उत्पादन के लिए सोलन जिला की बद्दी तहसील के बथेड़ गांव में मैसर्ज हरिपुर पेपर कम्पनी, दवा उत्पादन के लिए सोलन जिला की नालागढ़ तहसील के भाटियां गांव में मैसर्ज वैलैस फार्मास्यूटिक्लस प्राईवेट लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए उत्पादन व उपकरणों के लिए सोलन जिला के मलकुमाजरा गांव में मैसर्ज मोरपैन लैबोरेटरिज लिमिटेड, रेजर ब्लेड उत्पादन के लिए सोलन जिला के काथा में मैसर्ज जीलैट इंडिया लिमिटेड, एलपीजी स्टोव, पाईप निर्माण के लिए सोलन जिला के मानपुरा गांव में मैसर्ज मल्होत्रा ब्रदर्स, हैलमेट व अन्य उपकरणों के निर्माण के लिए सोलन जिला के झाड़माजरी में मैसर्ज जीएलएल इंडस्ट्रीज, एमएस बिल्लैट्स उत्पादन के लिए पांवटा साहिब के अंतर्गत पल्होड़ी गांव में मैसर्ज इंडिया स्टील कंटीनेंटल प्राईवेट लिमिटेड, दवा उत्पादन के लिए नाहन तहसील के अंतर्गत जोहड़ों गांव में मैसर्ज एमएमजी हैल्थ केयर, शहद उत्पादन के लिए बद्दी तहसील के मानकपुर गांव में मैसर्ज डाबर इंडिया लिमिटेड, प्लास्टिक सामग्री उत्पादन के लिए बद्दी में मैसर्ज टेस्नाटैक प्राईवेट लिमिटेड के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

जैसे ही भय आपके करीब आये, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिये...... चाणक्य

सम्पादकीय

केन्द्र की नीतियों पर सीधा प्रश्न चिन्ह है यह चुनाव परिणाम

अभी हुए दो राज्यों के विधान सभा चुनावों में हरियाणा में भाजपा को जनता ने सरकार बनाने लायक बहुमत नही दिया है। महाराष्ट्र में भी 2014 से कम सीटें मिली हैं। अन्य राज्यों में भी जहां जहां उप चुनाव हुए हैं वहां पर अधिकांश में सतारूढ़ सरकारों के पक्ष में ही लोगों ने मतदान किया हैं । यह चुनाव पांच माह पहले हुये लोकसभा चुनावों के बाद हुए हैं और इनके परिणाम उनसे पूरी तरह उल्ट आये हैं। क्योंकि लोकसभा में हरियाणा की सभी दस सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और इसी जीत के दम पर विधान सभा चुनावों में 90 में से कम से कम 75 सीटे जीतने का लक्ष्य घोषित किया था। अंबानी और अदानी की मलकीयत वाला मीडिया तो हरियाणा में कांग्रेस को चार पांच और महाराष्ट्र में आठ से दस सीटें दे रहा था। इसी मीडिया के प्रभाव में अधिकांश सोशल मीडिया भी इसी तरह के आकलन परोसने लग गया था। ऐसा शायद इसलिये था कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष को ऐसा अप्रत्याशित हार मिली थी जिसका किसी को भी अनुमान नही था। इस हार से विपक्ष एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर ही हताशा में चला गया था। एक बार फिर विपक्षी दलों के लोग पासे बदलने लग गये थे। इसी के साथ ईडी और सीबीआई की सक्रियता भी बढ़ गई कई महत्वपूर्ण नेताओं को जेल के दरवाजे दिखा दिये गये। कुल मिलाकर नयी स्थिति यह उभरती चली गई कि भाजपा अब कांग्रेस मुक्त नही बल्कि विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखने लग गई थी। विपक्ष की एकजुटता की संभावनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। कांग्रेस में राहूल गांधी एक तरह से हार के बाद अकेले पड़ गये थे क्योंकि हार कि जिम्मेदारी लेने के लिये पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़े नही हुआ। राहुल को अकेले ही यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी और त्याग पत्र देना पड़ा। इस त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के ही कई नेता अपरोक्ष में उनके खिलाफ मुखर होने लग गये थे। अन्य विपक्षी दल तो एकदम पूरे सीन से ही गायब हो गये थे। भाजपा संघ को कोई चुनौती देने वाला नजर नही आ रहा था।

भाजपा ने इसी परिदृष्य का लाभ उठाते हुये तीन तलाक विधेयक को फिर से संसद में लाकर पारित करवा लिया। इसके बाद जम्मू- कश्मीर से धारा 370 और 35 A को हटाकर जम्मू- कश्मीर को दो केन्द्र शासित राज्यों में बांट दिया। पूरी घाटी में हर तरह के नागरिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। पूरा प्रदेश एक तरह से सैनिक शासन के हवाले कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी नागरिक अधिकारों के हनन को लेकर आयी याचिकाओं पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। जिन बुद्धिजीवियों ने भीड़ हिसां के खिलाफ राष्ट्रपति को सामूहिक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया था उनके खिलाफ पटना में एक अदालत के आदेशों पर एफ आई आर तक दर्ज कर दी गयी। इससे सार्वजनिक भय का वातावरण और बढ़ गया। नवलखा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के करीब आधा दर्जन न्यायाधीशों द्वारा मामले की सुनवाई से अपने को अलग करना न्यायपालिका की भूमिका पर अलग से सवाल खड़े करता है। धारा 370 हटाने पर विश्व समुदाय के अधिकांश देशों द्वारा समर्थन का दावा इसी का परिचायक था कि '' King does no Wrong '' स्वभाविक है कि जब इस तरह के एक पक्षीय राजनीतिक वातावरण में कोई चुनाव आ जाये तो उनके परिणाम भी एक तरफा ही रहने का दावा करना कोई आश्चर्यजनक नही लगेगा।

ऐसे राजनीतिक परिदृश्य के बाद भी यदि जनता हरियाणा जैसे जनादेश दे तो यह अपने में एक महत्वपूर्ण चिन्तन का विषय बन जाता है। जब सब कुछ सता पक्ष क पक्ष में जा रहा था तो ऐसा क्या घट गया कि जनता विपक्ष के अभाव में भी ऐसा जनादेश देने पर आ गई। इसकी अगर तलाश की जाये तो यह सामने आता हैं कि राजनीतिक फैसलों का मुखौटा ओढ़कर जो आर्थिक फैसले लिये वह जनता पर भारी पड़ गये। जो सरकार चुनाव की पूर्व संधया पर किसानों को छः छः हजार प्रतिवर्ष देकर लुभा रही थी उसे सरकार बनते ही रिजर्व बैंक से 1.76 लाख करोड़ लेना पडा। इसके बाद 1.45 लाख करोड़ का राहत पैकेज कारपोरेट जगत को देना पड़ा और इसके बावजूद भी आर्थिक मन्दी में कोई सुधार नही आ पाया। आटोमोबाईल और टैक्सटाईल क्षेत्रों में कामगारों की छटनी नही रूक पायी उनके उतपादों की बिक्री नही बढ़ पायी। रेलवे, बी एस एन एल और एम टी एन एल मे विनिवेश की घोषणाओं से रोजगार के संकट उभरने के संकेतो से एकदम महंगाई का बढ़ना आम आदमी के लिये काफी था। उसे इतनी बात तो समझ आ ही जाती है कि मंहगाई और बेरोजगारी पर नियन्त्रण रखना हमेशा समय का सतारूढ़ सरकार का दायित्व होता है। जिसमें यह सरकार लगातार असफल होती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र की असफलताओं को ढकने के लिये जब प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनावों में विपक्ष को यह कह कर चुनौति दी कि यदि उसमें साहस है तो वह 370 को फिर लागू करने का दावा करे। इन विधान सभा चुनावों में धारा 370 विपक्ष का कोई मुद्दा ही नही था क्योंकि इसका चुनावों के साथ कोई सीधा संबंध ही नही था। लेकिन प्रधानमंत्री का विपक्ष को इस मुद्दे पर लाने का प्रयास करना ही यह स्पष्ट करता है कि सता पक्ष के पास अब ऐसा कुछ नही बचा है जो आर्थिक मन्दी पर भारी पड़ जाये। क्योंकि सारे धर्म स्थलों को भी यदि राम मन्दिर बना दिया जाये और सारे गैर हिन्दु भी यदि हिन्दु बन जायें तो भी बेरोजगारी और मंहगाई से जनता को निजात नही मिल पायेगी। क्योंकि 3000 करोड़ खर्च करके पटेल की प्रतिमा स्थापित करने से यह समस्याएं हल नही हो सकती यह तह है।

इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के आर्थिक परिवेश ने हर आदमी को हिलाकर रख दिया है। आम आदमी जान चुका है कि कल तक स्वदेशी जागरण मंच खडा करके एफडीआई का विरोध करने वाला सता पक्ष जब रक्षा जैसे क्षेत्र में एफडीआई को न्योता दे चुका है तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सब उसकी राजनीतिक चालबाजी से अधिक कुछ नही था। जंहा वैचारिक विरोध को देशद्रोह की संज्ञा दी जायेगी तो ऐसी राजनीतिक मान्यताएं ज्यादा देर तक टिकी नही रह सकती हैं। आज देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इस तरह के मुद्दों पर मुखर होने लग गये हैं और केन्द्र सरकार से उन अधिकारियों को केंन्द्र से वापिस राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है जो आंख बन्द करके उसकी हां में हां मिलाने को तैयार नही है। आज विपक्ष को इन उभरते संकेतों को समझने और अपनी हताशा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। क्योंकि पांच माह में ही इस तरह का खंडित जनादेश किसी भी गणित में सता के पक्ष में नही जाता है शायद इसीलिये प्रधानमंत्री को हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीयों के साथ खड़ा होना पड़ा है कि कहीं वह इस जनादेश का ठिकरा केन्द्र के सिर न फोड़ दें।

भारत में इस्पात की मांग बढ़ने की उम्मीद है

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में इस्पात की मांग में काफी वृद्धि हुई है और भविष्य में इसके और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है। प्रधान ने टोक्यो में इस्पात एक्सेस कैपेसिटी पर वैश्विक फोरम की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में इस्पात की मांग इसके क्षमता विस्तार की प्रेरक शक्ति होगी। उन्होंने कहा ''मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारत में तेजी गति से आर्थिक विकास और ढांचागत विकास के साथ इस्पात की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भविष्य में इसके और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अगले पांच वर्षों में अपने बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सब देश में इस्पात की मांग के लिए अच्छा है। हम इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 72 किलो प्रति व्यक्ति के वर्तमान निम्न स्तर से बढ़ाकर 2030 तक 160 किलो प्रति व्यक्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस्पात की भारत की मांग हमेशा इसके क्षमता विस्तार की प्रेरक होगी।''

प्रधान ने इस्पात अत्यधिक क्षमता के मुद्दे पर कहा कि भारत में इस्पात क्षेत्र नियंत्रण मुक्त है और यह बाजार ताकतों द्वारा प्रेरित होती है। जैसा कि यह अच्छी तरह विदित है कि भारत अत्यधिक क्षमता में योगदान नहीं देता या इससे प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा ''हम अत्यधिक क्षमता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति जागरुक और चैतन्य हैं और इसलिए इस फोरम द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का सम्मान करते हैं।''

मंत्री ने वैश्विक स्थिति पर इस्पात अत्यधिक क्षमता का 2015 के संकट के दौरान दुनियाभर के उद्योग पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा था। 2016-18 के दौरान संक्षिप्त सुधार के बाद एक बार फिर से वैश्विक इस्पात उद्योग कठिन समय से गुजर रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम 2015 की स्थिति के दोहराव से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। उन्होंने सूचना साझा करने की प्रक्रिया और उसके बाद समीक्षा करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास करने के लिए इस्पात अत्यधिक क्षमता पर वैश्विक फोरम के सदस्यों की सराहना की। प्रधान ने कहा कि विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समर्थन कदमों पर क्षमता एवं सूचना पर आंकड़ों को साझा करने की सदस्यों की इच्छा सराहना की हकदार है। उन्होंने कहा ''यह एक अनूठी पहली बार की कोशिश है सूचना साझा करने से वैश्विक इस्पात उद्योग के लिए उधार के लिहाज से बेहतर प्रतिक्रिया का निर्माण सक्षम हुआ है।'' उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास करने का आग्रह किया कि सभी कार्रवाइयां निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलनों की तर्ज पर हों।

प्रधान ने कहा कि बह्लन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने यह अनुशंसा की कि बाजार विकृतिकारी सब्सिडियों और समर्थन कदमों जो प्रतिस्पर्धा को विकृत करते हैं, की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसने यह भी सलाह दी कि सरकारों को बाजार में ऐसी विकृतियों के निर्माण के लिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि पारदर्शिता, बढ़ी हुई संचार व्यवस्था और सहयोग सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। वैश्विक फोरम सुसंगत इस्पात संबंधित मुद्दों पर विचार कर सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं आंतरिक रूप से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। प्रधान ने कहा ''इस्पात क्षेत्र की चिन्ताओं को दूर करने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।''

बैठक के दौरान, मंत्री ने यूरोपीय कमीशन के व्यापार की उप महानिदेशक सांद्रा गैलिना के नेतृत्व में यूरोपीयन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

समाज महिलाओं की प्रतिभा को उचित सम्मान दे

समय निरंतर बदलता रहता है, उसके साथ समाज भी बदलता है और सभ्यता भी विकसित होती है। लेकिन समय की इस यात्रा में अगर उस समाज की सोच नहीं बदलती तो वक्त ठहर सा जाता है। 1901 में जब नोबल पुरस्कारों की शुरुआत होती है और 118 सालों बाद 2019 में जब नोबल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा होती है तो कहने को इस दौरान 118 सालों का लंबा समय बीत चुका होता है लेकिन महसूस कुछ ऐसा होता है कि जैसे वक्त थम सा गया हो।

–डॉ. नीलम महेंद्र–

क्योंकि 2019 इक्कीसवीं सदी का वो दौर है जब विश्व भर की महिलाएं डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पायलट वैज्ञानिक से लेकर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ तक कि हाल ही के भारत के महत्वकांक्षी चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व करने वाली टीम में दो महिला वैज्ञानिकों के अलावा पूरी टीम में लगभग 30% महिलाएं थीं। कमोबेश यही स्थिति विश्व के हर देश के उन विभिन्न चनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी महिलाओं के होने की है जो महिलाओं के लिए वर्जित से माने जाते थे जैसे खेल जगत, सेना, पुलिस, वकालत, रिसर्च आदि।

सालों के इस सफर में यद्यपि महिलाओं ने एक लंबा सफर तय कर लिया लेकिन 2019 में भी जब नोबल जैसे अन्य प्रतिष्ठित पुरुस्कार पाने वालों के नाम सामने आते हैं तो उस सूची को देखकर लगता है कि सालों का यह सफर केवल वक्त ने तय किया और महिला कहीं पीछे ही छूट गई। शायद इसलिए 2018 में पिछले 55 सालों में भौतिकी के लिए नोबल पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक डोना स्ट्रिकलैंड ने कहा था, 'मुझे हैरानी नहीं है कि अपने विषय में नोबल पाने वाली 1901 से लेकर अब तक मैं तीसरी महिला हूँ, आखिर हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पुरूष ही पुरूष तो नजर आते हैं।' आश्चर्य नहीं कि 97% विज्ञान के नोबल पुरस्कार विजेता पुरूष वैज्ञानिक हैं। 1901 से 2018 के बीच भौतिक शास्त्र के लिए 112 बार नोबल पुरस्कार दिया गया जिसमें से सिर्फ तीन बार किसी महिला को नोबल मिला। इसी प्रकार रसायन शास्त्र, मेडिसीन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी लगभग यही असंतुलन दिखाई देता है। इनमें 688 बार नोबल दिया गया जिसमें से केवल 21 बार महिलाओं को मिला। अगर अबतक के कुल नोबल पुरस्कार विजेताओं की बात की जाए तो यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 892 लोगों को दिया गया है जिसमें से 844 पुरुष हैं और 48 महिलाएं। विभिन्न वैश्विक मंचों पर जब लैंगिक समानता की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी पुरस्कार के ये आंकड़े निश्चित ही वर्तमान कथित आधुनिक समाज की कड़वी सच्चाई सामने ले आते हैं। इस विषय का विश्लेषण करते हुए ब्रिटिश साइंस जर्नलिस्ट एंजेला सैनी ने 'इन्फीरियर' अर्थात हीन नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में विभिन्न वैज्ञानिकों के इंटरवियू हैं और कहा गया है कि वैज्ञानिक शोध खुद औरतों को कमतर मानते हैं जिनकी एक वजह यह है कि उन शोधों को करने वाले पुरूष ही होते हैं। अमेरिका की साइंस हिस्टोरियन मार्गरेट डब्लू रोसिटर ने 1993 में ऐसी सोच को माटिल्डा इफेक्ट नाम दिया था जब महिला वैज्ञानिकों के प्रति एक तरह का पूर्वाग्रह होता है जिसमें उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के बजाए उनके काम का श्रेय उनके पुरूष सहकर्मियों को दे दिया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी संभावना 95% होती है। क्लोडिया रैनकिन्स जो सोसाइटी ऑफ स्टेम वीमेन की सह संस्थापक हैं, इस विषय में उनका कहना है कि इतिहास में नेटी स्टीवेंस, मारीयन डायमंड और लिसे मीटनर जैसी कई महिला वैज्ञानिक हुई हैं जिनके काम का श्रेय उनके बजाए उनके पुरुष सहकर्मियों को दिया गया। दरअसल लिसे मीटनर ऑस्ट्रेलियाई महिला वैज्ञानिक थीं जिन्होंने न्यूक्लियर फिशन की खोज की थी लेकिन उनकी बजाए उनके पुरूष सहकर्मी ओटो हान को 1944 का नोबल मिला।

अगर आप इस कथन के विरोध में नोबल पुरस्कार के शुरुआत यानी 1903 में ही मैडम क्यूरी को नोबल दिए जाने का तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपके लिए इस घटना के पीछे का सच जानना रोचक होगा जो अब इतिहास में दफन हो चुका है। यह तो सभी जानते हैं कि रेडिएशन की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी दोनों ने मिलकर की थी लेकिन यह एक तथ्य है कि 1902 में जब इस कार्य के लिए नामांकन दाखिल किया गया था तो नोबल कमिटी द्वारा मैडम क्यूरी को नामित नहीं किया गया था, सूची में केवल पियरे क्यूरी का ही नाम था। पियरे क्यूरी के एतराज और विरोध के कारण मैडम क्यूरी को भी नोबल पुरस्कार दिया गया और इस प्रकार 1903 में वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक और फिर 1911 में रेडियम की खोज करके दूसरी बार नोबल पाने वाली पहली महिला बनीं।

स्पष्ट है कि प्रतिभा के बावजूद महिलाओं को लगभग हर क्षेत्र में कमतर ही आंका जाता है और उन्हें काबलियत के बावजूद जल्दी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। 2018 की नोबल पुरस्कार विजेता डोना स्ट्रिकलैंड दुनिया के सामने इस बात का जीता जागता उदाहरण हैं जो अपनी काबिलियत के बावजूद सालों से कनाडा की प्रतिष्ठित वाटरलू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ही कार्यरत रहीं थीं। इस पुरस्कार के बाद ही उन्हें प्रोफेसर पद की पदोन्नति दी गई।

आप कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में यह आम बात है। आप सही भी हो सकते हैं। किंतु मुद्दा कुछ और है। दरअसल यह आम बात तो हो सकती है लेकिन यह 'साधारण' बात नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ हम किसी साधारण क्षेत्र के आम पुरुषों की बात नहीं कर रहे बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के असाधारण वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, साहित्यकार पुरुषों की बात कर रहे हैं जिनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता और जिनका मानसिक स्तर उन्हें आम पुरुषों से अलग करता है। लेकिन खेद का विषय यह है कि महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता उस भेद को मिटाकर इन कथित इंटेलेकचुअल पुरुषों को आम पुरुष की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। पुरूष वर्ग की मानसिकता का अंदाजा ई –लाइफ जैसे साइंटिफिक जर्नल की इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है कि केवल 20% महिलाएं ही वैज्ञानिक जर्नल की संपादक, सीनियर स्कॉलर और लीड ऑथर जैसे पदों पर पहुंच पाती हैं। आप कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या और उपस्थिति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। इस विषय पर भी कोपेनहेगेन यूनिवर्सिटी की लिसोलेट जौफ़ेड ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने यू एस नेशनल साइंस फाउंडेशन से इस क्षेत्र के 1901 से 2010 तक के जेंडर आधारित आंकड़े लिए और इस अनुपात की तुलना नोबल पुरस्कार पाने वालों की लिंगानुपात से की। नतीजे बेहद असमानता प्रकट कर रहे थे। क्योंकि जिस अनुपात में महिला वैज्ञानिक हैं उस अनुपात में उन्हें जो नोबल मिलने चाहिए वो नहीं मिलते।

जाहिर है इस प्रकार का भेदभाव आज के आधुनिक और तथाकथित सभ्य समाज की पोल खोल देता है। लेकिन अब महिलाएँ जागरूक हो रही हैं। वो वैज्ञानिक बनकर केवल विज्ञान को ही नहीं समझ रहीं वो इस पुरूष प्रधान समाज के मनोविज्ञान को भी समझ रही हैं। वो पायलट बनकर केवल आसमान में नहीं उड़ रहीं बल्कि अपने हिस्से के आसमाँ को मुठ्ठी में कैद भी कर रही हैं। यह सच है कि अब तक स्त्री पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर सदियों का सफर तय कर यहाँ तक पहुंची है, इस सच्चाई को वो स्वीकार करती है और इस साथ के लिए पुरूष की सराहना भी करती है। लेकिन अब पुरुष की बारी है कि वो स्त्री की काबिलियत को उसकी प्रतिभा को स्वीकार करे और उसको यथोत्तचित सम्मान दे जिसकी वो हकदार है।

मंत्रिमण्डल ने दी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना को मंजूरी

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में आयुष नीति-2019 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत लोगों को किफायती दरों पर आयुष सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों को स्तरोन्नत किया जाएगा। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति को स्तरोन्नत एवं सुदृढ़ कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार के लिए प्रेरित करना है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।

प्रदेश सरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य आयुष नीति लेकर आई है जिसके अंतर्गत आयुष एवं आरोग्य क्षेत्र में संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है। इस नीति के तहत आयुष थेरेपी यूनिट को स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसमें भूमि पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा तथा ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपये होगा। सात वर्षों के लिए 75 प्रतिशत की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचली लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी तथा चयनित परियोजनाओं में लीज रेंट और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने नई आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति-2019 को भी मंजूरी प्रदान की है ताकि हिमाचल प्रदेश को इन क्षेत्रों में निवेश के लिए देश का प्रमुख क्षेत्र बनाया जा सके। इस नीति में अधोसंरचना प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है जो आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

इसी प्रकार वहन योग्य आवासीय नीति-2019 को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की। इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है।

बैठक में हि.प्र. काश्तकारी एवं भू-सुधार नियमों के नियम 38(ए)(3)(एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन ईकाइयां स्थापित करने के इच्छुक गैर कृषकों को राज्य में भूमि खरीदने के उद्देश्य से अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्यटन विभाग के संशोधित मापदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इच्छुक निवेशक को अपनी पर्यटन परियोजना की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट पर्यटन विभाग के निदेशक को सौंपनी होगी, जिसके लिए वह अनिवार्यता प्रमाण पत्र चाहता है। विभागीय निदेशक संबंधित पर्यटन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आकलन करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की ताकि राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र का विनियमन करने के साथ-साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्राधिकरण के प्रबन्धन के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 46 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के अपार अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रदेश के पारम्परिक हस्तशिल्प, हथकरघा एवं शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना युवाओं को अपनी दक्षता मे स्तरोन्नयन करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें पारम्परिक कौशल से जोड़ने और अपने उत्पादों

की बिक्री के लिए भी सहायक सिद्ध होगी।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की देश के प्रति दी गई सेवाओं के सम्मान में शिमला और मनाली में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने नशे के चंगुल में फंसे युवाओं के पुनर्वास के उद्देश्य से बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, शिमला और नूरपुर में एकीकृत पुनर्वास केन्द्र खोलने का निर्णय लिया। इन केन्द्रों में नशे से प्रभावित युवाओं के उपचार की सुविधा होगी।

बेसहारा छोड़े गए पशुओं की समस्या के समाधान के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की जुब्बल तहसील के अंतर्गत अंटी पटवार वृत के मोहाल चिंग धर्माणा में पशु पालन विभाग की वन भूमि को श्रीमद्भगवत गीता प्रचार एवं जन जागरण सभा, ननखड़ी, जिला शिमला को गौसदन के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

बैठक में मंडी जिला के ढीम कटरू, धरोट, सरोआ, बागाचनोगी, मुरह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में राजकीय रेशम उत्पादन केन्द्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इन केन्द्रों के समुचित प्रबन्धन के लिए सेरीकल्चर इंस्पेक्टर और माली/बेलदार के सात-सात पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया।

उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर विस्तार अधिकारी (उद्योग) के छः पद भरने का निर्णय लिया गया है।

बिलासपुर जिला के झंडुता में नया फायर सब-स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत कांडा-बगशयाड़, शरण तथा मुरहग पंचायतों को पुलिस थाना जंजैहली में शामिल करने का निर्णय लिया है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नैरचौक में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संकाय के 15 पद नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार के तीन पदों के सृजन एवं इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अतिरिक्त बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला के हरिपुर में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल सृजित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार ऊना जिला में बंगाणा लोक निर्माण विभाग मण्डल के अंतर्गत डेरा बाबा रूदरू (बसाल) में भी लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल खोलने का निर्णय लिया गया।

मंडी जिला की सुन्दरनगर तहसील के अंतर्गत डेहर में निरीक्षण कुटीर/विश्राम गृह में अतिरिक्त कमरों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. स्टेट एजुकेशन सोसायटी के तकनीकी स्टॉफ का लोक निर्माण एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में विलय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सहायक अभियन्ता नागरिक, कनिष्ठ अभियन्ता नागरिक और कनिष्ठ प्रारूपकार के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एक मुश्त छूट दी जाएगी।

बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा और धीरा तथा चम्बा जिला के पांगी के उपमण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नामकरण जल शक्ति विभाग के रूप में करने को अपनी सहमति प्रदान की।

प्रदेश निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के 13 पद भरने का निर्णय लिया गया है। यह पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

बैठके में मंडी में न्यू डवेल्पमेंट बैंक के लिए इंजीनियर-इन-चीफ (प्रोजेक्ट) के अंतर्गत परियोजना प्रबन्धन इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए कांगड़ा जिला के फतहपुर से इंजीनियर-इन-चीफ (प्रोजेक्ट) का पद मौजूदा स्टॉफ सहित स्थानान्तरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना को भी पूरे स्टाफ के साथ शिमला से मंडी स्थानान्तरित किया जाएगा ताकि परियोजना प्रबन्धन इकाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देते हुए नगर नियोजन विभाग में योजना अधिकारियों के तीन पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बागवानी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर स्किल्ड ग्राफट्र्स के नौ पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के चार पद भरने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के इंटर्न का वजीफा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह करने को सहमति प्रदान की।

प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों जिनमें एनएफएसए श्रेणियां भी शामिल हैं को फोरटीफाईड गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल की बैठक में 31 मार्च, 2019 और 30 सितम्बर, 2019 को आठ वर्ष का लगातार सेवाकाल पूरा कर चुके सभी अशंकालिक कर्मचारियों दैनिक भोगी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग के जल वाहक भी शामिल होंगे।

बैठक में सरकारी क्षेत्र में करूणामूलक आधार पर रोजगार प्राप्त करने के लिए आय सीमा को 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 34 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार की माता स्वर्णा देवी परमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

युवाओं को अपनी संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना हमारा उत्तरदायित्व:डॉ.सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि भारत को अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है और हम सभी यह नैतिक कर्तव्य है कि युवा पीढ़ी को संस्कृति, लोक परंपराओं और नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान किया जाए। डॉ. सैजल सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में स्माइलेक्स ग्रुप द्वारा आयोजित धार्मिक समारोह को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. सैजल ने कहा कि अपनी संस्कृति का ज्ञान न केवल जरूरी है अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक एवं नैतिक रूप से सबल भी बनता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कृति का प्रथम ज्ञान अपने घर से प्राप्त होता है। इस दिशा में अभिभावकों को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि संस्कृति से विमुख युवा पीढ़ी देश के पतन का कारण बन सकती है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अपनी संस्कृति को जाने और सभी तक भारत की अनेकता में एकता की विविध संस्कृति की जानकारी पहुंचाएं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। उनके इस झुकाव को अपनी संस्कृति की जानकारी प्रदान कर ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम अब भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को अपना रहा है और हमें अपने युवाओं को भारतीय संस्कृति के मजबूत पक्ष से अवगत करवाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। युवाओं को संस्कृति के तार्किक और वैज्ञानिक पक्ष से रूबरू करवाना हमारा उत्तरदायित्व है।

डॉ. सैजल ने इस अवसर पर सभी से आग्रह किया कि युवाओं को नशे से दूर रखने में एकजुट होकर कार्य करें।

दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी तथा पूर्व विधायक विनोद चंदेल ने इस अवसर पर अपने विचार रखें।

स्माइलेक्स ग्रुप के अध्यक्ष मुकुल बिहारी गोयल ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर सार्थक रंगमंच चंडीगढ़ के कलाकारों द्वारा विनीत शर्मा के निर्देशन में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक को सभी द्वारा सराहा गया।

डॉ. राजीव सैजल की धर्मपत्नी रेनु सैजल, हिमाचल गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, भाजपा के प्रदेश सचिव डॉ. श्रीकांत शर्मा व कैप्टर डीआर चंदेल, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मेला राम चंदेल, दून भाजपा मंडल के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय खुराना एवं अन्य सदस्य, मुक्ता गोयल, विभोर गोयल, बाल मोहन शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।

संजय कुंडू ने केन्द्रीय मंत्रियों से इन्वेस्टर मीट में सहयोग के लिए आग्रह किया

शिमला/शैल। प्रधान सचिव संजय कुंडू ने नई दिल्ली में वित्त एवं कार्पोरेट मामलों के केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की तथा उनसे धर्मशाला में आयोजित 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

अनुराग ठाकुर ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की तथा संयुक्त अरब अमीरात के साथ आयोजित होने वाले सत्र की अध्यक्षता करने को अपनी सहमति जताई। संयुक्त अरब अमीरात इस आयोजन में भागीदार देश है।

इसके उपरान्त, संजय कुंडू केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले तथा उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के कार्यक्रम के उद्देश्य व लक्ष्यों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने इस आयोजन के लिए मंत्रालय से समर्थन देने के लिए भी अनुरोध किया।

मंत्री ने मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग और आयोजन के व्यापक प्रचार का आश्वासन दिया।

संजय कुंडू ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे तथा आकाशवाणी के महानिदेशक एफ. शहरेयार से मुलाकात की। दोनों ने इस मेगा इवेंट के पूर्ण समर्थन तथा व्यापक प्रचार का आश्वासन दिया।

संजय कुंडू ने भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ. अहमद अबाना से मुलाकात की तथा उनसे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की क्योंकि यह देश इस मीट में एक भागीदार देश है।

डॉ. अलबाना ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस आयोजन में भाग लेंगे तथा उनके देश का इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग रहेगा।

उप आवासीय आयुक्त, विवेक महाजन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

आपदा प्रबंधन के लिए 48,390 युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी हिमाचल के निर्माण के लिए सभी सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा, प्रौद्योगिकी संचालित और समुदाय आधारित रणनीति विकसित कर प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

वह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर राज्यों के हितधारकों के लिए ''पहाड़ी शहरों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियां'' विषय पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के सहयोग से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और हि.प्र. विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद् कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक जोखिमों जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बर्फीले तूफान और हिमस्खलन, सूखे आदि और मानव निर्मित जोखिमों जैसे बांधों का टूटना, आग, दुर्घटनाओं सहित जैविक, औद्योगिक और खतरनाक रसायन शामिल हैं। इसके अलावा, भूकंपीय क्षेत्र पांच में आने के कारण हिमाचल में भूकंप के खतरे और भी बढ़ जाते हैं इसलिए घरों को भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करके इसे कम करने के लिए कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि लोग अभी भी ऐसे घरों में रह रहे हैं जो मजबूत स्थिति में नहीं हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सुरक्षित घरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 16,130 बढ़ईयों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पताल सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक योजना बनाई गई है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दस से पंद्रह युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इस प्रकार पहले चरण में 48,390 युवाओं को बचाव कार्य और पीड़ितों को प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएमए ने पिछले साल आसामयिक हिमपात के कारण चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में फंसे 4000 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए 'ऑपरेशन व्हाइट हिमालया' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूल सुरक्षा परियोजना को भी मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी और शिक्षण संस्थानों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। भारत सरकार ने राज्य के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बटालियन को भी मंजूरी दी है और राज्य सरकार अपनी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने पर भी काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घटनाओं को कम करने और इन्हें रोकने की तैयारियों के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करके एक आपदा रोधी हिमाचल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राजनीतिक और कानूनी प्रतिबद्धता के अतिरिक्त, वैज्ञानिक ज्ञान, चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिमों के शमन के लिए प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के अलावा हितधारकों की सक्रिय भागीदारी भी इसमें आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय भी महत्वपूर्ण है। राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष स्थापित करने पर विचार करेगा, ताकि प्रभावित समुदाय को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए धनराशि जारी की जा सके।

उन्होंने इस अवसर पर एसडीएमए द्वारा तैयार स्कूल प्रबंधन के दिशा-निर्देशों पर एक पुस्तिका, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित निर्माण प्रथाओं पर दो वीडियो जारी किए।

शहरी विकास, आवास और नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में घरों के निर्माण में पारंपरिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्शों के अनुसार गृह निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए आवेदन के एक माह के भीतर मंजूरी प्रदान की जा रही है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि भवनों का निर्माण नियमानुसार करें ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने देश में रेरा अधिनियम लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्य सचिव डॉ.श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि सचिवालय, उपायुक्त कार्यालयों, दमकल केंद्रों, पुलिस थानों, दूरसंचार नेटवर्क, महत्वपूर्ण पुलों और पानी के टैंकों आदि जैसे जीवन रेखा भवनों को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तत्काल राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने सड़क और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के कारण निकलने वाले मलबे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी बल दिया क्योंकि यह भूस्खलन और बाढ़ का कारण बनता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने कहा कि विकास कार्य इस प्रकार होने चाहिए कि उनसे आपदाओं का खतरा न बढ़े। उन्होंने कहा कि एक आपदा कई आपदाओं की श्रृंखला बन जाती है, इसलिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कम से कम हिमालयी राज्यों को अपने आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी और संचार नेटवर्क में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए आगे आना चाहिए।

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि एनडीएमए की हिमालयी राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ये राज्य अधिकतम प्राकृतिक आपदाओं के शिकार बनते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जान-माल का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम सक्रिय कदम उठाने पर बल देना होगा।

आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर और महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य प्रो. रवि कुमार सिन्हा ने पहाड़ी राज्यों में आपदा जोखिम प्रबंधन और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के जोखिम पर एक विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

राजस्व-आपदा प्रबंधन के निदेशक एवं विशेष सचिव डी.सी. राणा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्राधिकरण का प्रयास सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय इस कार्यशाला में खतरनाक आपदाओं के मूल्यांकन और प्रबंधन पर चार तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें पहाड़ी शहरों में भवन उप-कानूनों के अनुपालन में सुधार, आपदा न्यूनीकरण, तैयारियों और आपदा प्रतिक्रिया व वसूली में सुधार पर चर्चा होगी।

महापौर कुसुम सदरेट, सचिव शहरी विकास सी. पालरासु, शिमला और मंडी के उपायुक्त, एनजीआरआई हैदराबाद, जीएसआई चंडीगढ़, एनआईटी हमीरपुर, आईआईटी मद्रास, बाम्बे और मंडी, आईएमडी नई दिल्ली जैसे कई संस्थानों के प्रतिनिधि, विज्ञानी और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख वैज्ञानिक कार्यशाला में उपस्थित थे।

" Bank of the State - For the State"

THE HIMACHAL PRADESH STATE COOPERATIVE BANK LTD; HO SHIMLA

(Scheduled Bank)

1st Cooperative Bank of the Country on 100% C.B.S.

SH. JAI RAM THAKUR
HON'BLE CHIEF MINISTER

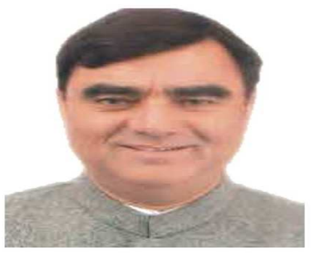

SH. KHUSHI RAM BALNATAH
CHAIRMAN

Changing lives through Social banking Since 1953

Highlights:
- 218 Branches & 23 Extension Counters fully on CBS mode
- 90 ATM's
- Bank is continuously profit earning & dividend paying organisation
- 1st Prize in overall Performance
- Best Performance Award for imparting quality training through training institute ACSTI,Sangti (Summerhill)

Deposit Schemes
- Pygmy deposits
- Paanch Saal main Lakhpati Yojna
- Himpunernivesh Deposits
- Sarvapriya Deposit
- Recurring Deposit

Facilities Available
- ATM Facility
- Mobile Banking
- SMS Alerts
- Rupay Debit Card
- RTGS/NEFT
- KCC Rupay Cards
- Lockers
- Implementing bancassurance Business
- Implementing PMJDY, PMJJBY, APY & PMSBY

Maximum Interest Rates on Deposits

Loans Schemes
- Kisan Credit Card Scheme
- House Loan
- Vehicle Loan
- Personal Loan
- Education Loan
- Self Employment Loan
- Hotel/Motel
- Farm Plus Loan Scheme

KHUSHI RAM BALNATAH
CHAIRMAN

RuPay www.hpscb.com A GRADE BANK

DR. PANKAJ LALIT (H.A.S)
MANAGING DIRECTOR

- Highest Rate of interest on deposits to Senior Citizens
- Quick disposal • Low margin requirements

Toll Free No.: 1800-180-8090

For more details- Visit our nearest Branch today or Log on to www.hpscb.com
Phone: 0177-2804492, 2651051, 2651053

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

उद्घाटन के दिन बिल्डिंग पूरी तैयार भी हो यह जरूरी नही के.एन.एच.में यह सच आया सामने

1924 में स्थापित हुये इस अस्पताल में अभी भी नही है एक्स-रे जैसी सुविधायें

शिमला/शैल। प्रदेश के सबसे बड़े कमला नेहरू महिला शिशु अस्पताल को आज तक एक्स-रे सुविधा उपलब्ध नही हो पायी है। जबकि इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और यह एक लेडी रिड़िंग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से इसका संचालन इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला के अधीन है। इसमें प्रतिदिन सैंकड़ों के हिसाब से महिला मरीज आते हैं। क्योंकि प्रसव का यह सबसे बड़ा केंद्र है। स्वभाविक है कि जब ऐसी गर्भवती महिलायें यहां आती है तो उनके परीक्षण के बाद उन्हें कई

तरह के टैस्ट आदि करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन इस तरह के सारे टैस्ट यहां नही हो पाते हैं और उनके लिये मरीजों को आईजीएमसी भेजा जाता है। आईजीएमसी का कमला नेहरू अस्पताल से पैदल एक घन्टे से अधिक का रास्ता है और बस या अपने वाहन से जाने में यह रास्ता 8 से 10 किलोमीटर पड़ जाता है। ऐसे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों को इसके लिये कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। खून की जांच से संबंधित भी अधिकांश टैस्ट मैडिकल कॉलिज की लैब में ही होते हैं। ऐसे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यदि मरीज के साथ एक ही तामीरदार आया हो तो वह सैंपल लेकर मैडिकल कॉलेज जायेगा या मरीज की देखभाल के लिये उसके साथ रहेगा। एक्स-रे तक की सुविधा अभी तक यहां उपलब्ध नही है। एक्स- रे तो आस पास की प्राईवेट लैब में भी उपलब्ध नही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि एक और तो सरकार आयुषमान भारत और हिमकेयर जैसी स्वस्थ्य योजनाएं चलाकर हर गरीब आदमी को निशुल्क चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने का दावा कर रही है लेकिन मरीजों को व्यवहारिक रूप से किस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान ही नही है।

कमला नेहरू अस्पताल के पुराने भवन की हालत अत्यन्त दयनीय है इसे तोडकर नये सिरे से बनाने की आवश्यकता है। इस संद्धर्भ में करीब बीस वर्ष पहले इसमें एक नया पांच मजिलां ब्लॉक जोड़ा गया था और आज उसी में अस्पताल का मुख्य काम चल रहा है। इसी कड़ी में 2013 में इसमें एक और ब्लॉक जोड़ने के लिये शिलान्यास किया गया था। यह सात मंजिला ब्लॉक बनकर तैयार भी हो गया है परन्तु इसके भीतर का काफी काम होना बाकी है। लेकिन हमारे राजनेताओं को अधूरे भवनों का उदघाटन करने की जल्दबाजी रहती है और इसी सनक से इस ब्लॉक का उदघाटन फरवरी 2019 में कर दिया गया। क्योंकि उसके बाद लोक सभा चुनाव आने थे और उनमें इसका श्रेय लिया जाना था।

जबकि उदघाटन का अर्थ होता है कि उसी दिन से भवन उपयोग में आ गया है। लेकिन यहां पर व्यवहारिक स्थिति यह है कि पूरे भवन को उपयोग में लाने के लिये अभी एक वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। यही नही जिस पांच मजिला ब्लॉक में अस्पताल का मुख्यकाम चल रहा है उस तक पहुचने वाले मार्ग पर काफी अरसा पहले भूसखलन हुआ था और उसके कारण बड़ी ऐंबुलैन्स भी वार्ड तक ले जाना कठिन हो गया था। उससे अवरूद्ध हुये मार्ग को अभी तक पूरी तरह प्रशासन साफ नही कर पाया है। इससे स्वास्थ्य जैसे संस्थानों के प्रति भी प्रशासन की संवेदनशीलता का पता चल जाता है।

इसमें दिलचस्प तो यह है कि कमला नेहरू अस्पताल एकदम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास ओकओवर के साथ लगता है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी स्वंय डॉक्टर है और कई अवसरों पर यहां मरीजों को फल-मिठाईयां आदि बांटने के उद्देश्य से यहां आती रहती हैं। बल्कि जब वह अस्पताल में आती हैं तो पूरा प्रबन्धन उनके स्वागत में शामिल रहता है। लेकिन अभी तक इस सच्च की ओर मुख्यमन्त्री की डॉक्टर पत्नी का भी ध्यान नही गया है कि इस अस्पताल में बहुत सारी चिकित्सीय सुविधाओं की कमी है और मुख्यमन्त्री से अधूरे ही भवन का उदघाटन करवा दिया गया है।

क्या राठौर हार के कारणों की

पृष्ठ 1 का शेष

उपचुनावों में आचार सहिंता के उल्लंघन के आरोप तो लगाती रही लेकिन इसी मुद्दे पर चुप रही कि चुनाव के दौरान भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अन्य विभागों की जिम्मेदारी कैसे रही। क्योंकि यह स्वभाविक है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हर समय मुख्यसचिव के आदेशों निर्देशों से बंधा हुआ है वह आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर निष्पक्ष कैसे रह सकता है।

इसी के साथ कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के मनाली के एक पर्यटक कारोबारी को 65 करोड़ के ऋण मामले में जिस तरह से ऋणकर्ता ने शान्ता कुमार के विवेकानन्द ट्रस्ट को इस ऋण से पन्द्रह लाख के दान देने का चैक सामने आया और शान्ता ने इसे लेने से इन्कार कर दिया उससे जहां ऋण लेने वाले की जायज पात्रता पर स्वाल खड़े होते थे वहीं पर यह सवाल भी अहम हो जाता है कि ऋण देने वाले बैंक का चेयरमैन भी इसी ट्रस्ट का एक ट्रस्टी है। यही नही पिछले दिनों जिस वायरल पत्र में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और इस पर आदेशित जांच में भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री का मोबाइल फोन तक पुलिस ने जब्त किया है। यह ऐसे मुद्दे है जिनका सरकार के पास जबाव नही है लेकिन पूरे चुनाव में कांग्रेस ने इन मुद्दों पर ढ़ग से आवाज नही उठायी। कांग्रेस ने अपने को इसी तक सीमित रखा कि सरकार सता का दुरपयोग कर रही है और धन बल का इस्तेमाल हो रहा है। आज के परिदृश्य में ऐसे आरोपों की कोई अहमियत नही रह जाती है। जबकि यह एक स्थापित सत्य है कि जब राजनिति में धन का प्रयोग हो रहा हो तो उस समय उसको भ्रष्टाचार के प्रमाणिक आरोपों से ही हराया जा सकता है। फिर राठौर तो एक ऐसा चेहरा है जिसके अपने खिलाफ इस तरह का कोई आरोप नही है। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राठौर इस मोर्चे पर असफल क्यों रहे। क्या जो लोग राठौर को लेकर आये थे वही भीतर से उसके साथ नही हैं। क्योंकि जो मुद्दे पार्टी के प्रवक्ताओं को उठाने चाहिये थे वह अध्यक्ष उठा रहा था। एक तरह से अध्यक्ष व प्रवक्ताओं का काम राठौर को ही करना पड़ रहा था।

इस उप चुनाव में जब सुधीर के भाजपा में जाने की चर्चाएं पहली बार उठी थी तभी से संगठन को इस बारे में गंभीर हो जाना चाहिये था। सुधीर वीरभद्र के निकटस्थ रहे हैं लेकिन जहां आज वीरभद्र धर्मशाला पर जांच की मांग कर रहे हैं उस समय सुधीर को लेकर यह सवाल उठे थे तब वह क्यों खामोश रहे इस पर अभी तक कुछ सामने नही आया है। जबकि अब धर्मशाला की भंग ईकाई के लोग अपरोक्ष में सुधीर और जी एस बाली के द्वन्द की ओर इस प्रकरण को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रकरण में राठौर क्या भूमिका निभाते हैं इस पर भी सब की निगाहें रहेंगी। यदि आने वाले समय में राठौर संगठन में अनुभवी प्रवक्ता लेकर नही आ पाते हैं तो उनके लिये इस स्थान पर बने रहना आसान नही रहेगा क्योंकि आगे चलकर केवल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही सरकार को घेरा जा सकेगा।

चुनाव परिणामों ने

पृष्ठ 1 का शेष

जवाब तल्वी सही में ही हो जाती है तब पार्टी के अन्दर कई और सच सामने आयेंगे। इस जवाब तल्वी के साथ ही कांगड़ा से मंत्री पद के दावे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जायेंगे। इसी के साथ यह सवाल भी चर्चा में आयेगा कि पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राकेश चौधरी और दयाल प्यारी को क्या पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का आर्शीवाद तो हासिल नही था। क्योंकि जितने वोट यह विद्रोही केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का विरोध सहते हुये ले गये हैं उससे प्रमाणित हो ही जाता है कि पार्टी में निष्ठा से काम करने वालों के लिये कोई जगह नही रह गयी है निष्ठा का स्थान जब नेतृत्व के गिर्द परिक्रमा ले लेता है तब ईमानदार कार्यकर्ता के पास बगावत के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नही रह जाता है।

अब इन उपचुनावों के बाद दो मंत्री पदों के साथ ही विभिन्न निगमों बोर्डों में भी ताजपोशियां होनी है। इनमें यह सामने आ जायेगा कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कहां क्या स्थान हासिल हो पाता है। फिर जो लोग एक समय हिलोपा और आम आदमी पार्टियों में चले गये थे उनकी वापसी तो भाजपा में हो गई है लेकिन भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के सम्मान के अतिरिक्त उन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नही हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस आदि के जिन नेताओं के भाजपा में शामिल होने की परोक्ष/अपरोक्ष चर्चा चली थी और इस चर्चा के संकेत एक समय पार्टी अध्यक्ष सतपाल सती तक ने दे दिये थे अब उनकी भूमिका और रिश्ते भाजपा के साथ क्या मोड़ लेते हैं यह देखना भी दिलचस्प होगा। ऐसे में इस उपचुनाव के परिणाम प्रदेश भाजपा के लिये कई ऐसे सवाल खड़े कर गये हैं जिनके उत्तर तलाशना आसान नही होगें।